रेलवे द्वारा दिल्ली में उच्च अधिकारियों के लिये बड़े बंगलों का निर्माण

*367. **सरदार जेगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा रेलवे के उच्च अधिकारियों के लिये दिल्ली में बड़े बंगले बनाने का निर्णय लिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने बंगले बनाये जाने की योजना है और इस योजना के क्रियान्वयन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) खासकर इसी समय इन बंगलों का निर्माण कराये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय की सहमति से दिल्ली में कुल 119 लाख रुपये की अनुमानित लागत से रेलवे बोर्ड के सदस्यों, जो भारत सरकार के सचिव स्तर के हैं, के लिये तीन शयन-कक्षों वाले 7 मकान और अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए 5 फ्लैटों का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया है।

(ग) सामान्य पूल में उपयुक्त मकानों की भारी कमी के कारण, इन वरिष्ठ अधिकारियों को इस समय अपनी सामान्य पात्रता से बहुत नीचे के मकानों में रहना पड़ रहा है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय द्वारा इन मकानों के बनाये जाने से, सामान्य पूल पर पड़ रहे दबाव में कुछ हद तक राहत प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दी गई वित्तीय सहायता/अनुदान

*369. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985, 1986 और 1987 के दौरान वर्षवार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता/अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने कुल पदों के लिये विशेष सहायता/अनुदान की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को निम्नलिखित योजनागत और योजनेतर अनुदान दिए गए थे

(रुपये लाखों में)

	1985-86	1986-87	1987-88
योजनागत	327.24	335.81	525.18
योजनेतर	2532.88	2841.73	3423.93

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of railway land for commercial purposes in Bombay

*370. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railways are considering a proposal to allot open, unused Railway land to outsiders for commercial purposes on nominal rent in Bombay;